साप्ताहिक
Live not just breaTHE

दि कार्मिक पोस्ट

MPHIN/2015/63220
MP/IDC1528/22-23

Global School Of Excellence, Obedullaganj

Email- thekaarmiicpost@gmail.com

वर्ष : 11, अंक : 16 (प्रति बुधवार), इन्दौर, 19 नवंबर 2025 से 25 नवंबर 2025 पेज : 8 कीमत : 3 रुपये

भारत पेश करेगा नए संशोधित जलवायु लक्ष्य कॉप-30 में भूपेंद्र यादव का ऐलान

नई दिल्ली। भारत 2035 के लिए अपने नए संशोधित जलवायु लक्ष्य (एनडीसी) और द्विवार्षिक पारदर्शिता रिपोर्ट (बीटीआर) को पेरिस समझौते के अनुरूप समय पर जमा करेगा। इस बात की घोषणा केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने 17 नवंबर को ब्राजील के बेलेम शहर में चल रहे कॉप-30 सम्मेलन के उच्चस्तरीय सत्र में की है।

यह कदम भारत की दीर्घकालिक जलवायु रणनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जा रहा है, खासकर तब जब वार्ताकार बेलेम पैकेज को अंतिम रूप देने के लिए एक निर्णायक सप्ताह में प्रवेश कर रहे हैं। गौरतलब है कि राष्ट्रीय निर्धारित योगदान यानी एनडीसी पेरिस समझौते का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। इनमें हर देश बताता है कि वह अपने उत्सर्जन कैसे कम करेगा और जलवायु परिवर्तन के असर से कैसे निपटेगा। हर पांच साल में देश अपने एनडीसी, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसी) सचिवालय को भेजते हैं। अब तक 198 में से 100 से ज्यादा देश अपने एनडीसी का तीसरा अपडेट सबमिट कर चुके हैं। वहीं द्विवार्षिक पारदर्शिता रिपोर्ट (बीटीआर) सभी देशों के लिए एक पारदर्शी तरीका है जिसके जरिए वे पेरिस समझौते के तहत अपनी जलवायु कार्रवाई की जानकारी देते हैं। इससे देशों के बीच भरोसा बढ़ता है और जलवायु वित्त और तकनीक जुटाने में मदद मिलती है। इस रिपोर्ट में किसी देश के ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन, जलवायु अनुकूलन के प्रयास, और उसे मिली या जरूरी सहायता का विस्तृत विवरण होता है। इससे दुनिया भर के देशों की तुलना करना और उन्हें जवाबदेह बनाना आसान होता है। इसके साथ ही बीटीआर, देशों को अपनी योजनाओं की खामियां पहचानने, अच्छी प्रक्रियाएं अपनाने और भविष्य की जलवायु नीतियों को बेहतर बनाने में भी मदद करती है। भारत की ओर पक्ष रखते हुए भूपेंद्र यादव ने कहा कि कॉप-30 को कार्रवाई के सम्मेलन और वायदों को पूरा करने वाला कॉप के रूप में याद किया जाना चाहिए। पेरिस समझौते के 10 साल पूरे होने पर उन्होंने जोर दिया कि अब दुनिया को वादों से आगे बढ़कर ठोस कार्रवाई की ओर बढ़ना होगा। उन्होंने ब्राजील को सम्मेलन की मेजबानी के लिए धन्यवाद देते

हुए कहा कि अमेजन का यह हिस्सा हमारे ग्रह की जैविक संपदा का जीवंत प्रतीक है और जलवायु महत्वाकांक्षा, समानता और वैश्विक भरोसा बहाल करने वाले कॉप के लिए बिल्कुल उपयुक्त स्थान है। यह कॉप ऐसे समय हो रहा है जब दुनिया डेढ़ डिग्री के लक्ष्य की राह से पूरी तरह भटक चुकी है। वैश्विक जलवायु व्यवस्था भारी दबाव में है। 2023 के ग्लोबल स्टॉकटेक ने साफ कर दिया कि दुनिया उत्सर्जन में कटौती, जलवायु वित्त और अनुकूलन तीनों मोर्चों पर पिछड़ रही है। विकासशील देश बार-बार गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें पर्याप्त वित्त नहीं मिल रहा, कर्ज का बोझ बढ़ रहा है और मौजूदा अंतरराष्ट्रीय सहयोग प्रणाली उनकी जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रही। ऐसे माहौल में, भारत खुद को ब्रिज बिल्डर यानी पुल के रूप में पेश कर रहा है, जो जलवायु न्याय, समान अवसर और तकनीक की सब तक आसान पहुंच की वकालत करता है। बेलेम में दिया भारत का बयान, पहले की जी20 और कॉप वार्ताओं का स्वाभाविक विस्तार है, जहां भारत लगातार अधिक जलवायु वित्त, सस्ते ऋण और देशों की अलग-अलग जिम्मेदारियों की स्पष्ट स्वीकार्यता की मांग उठाता रहा है। यादव ने विकसित देशों से कड़े शब्दों में कहा है कि वे अपने नेट-जीरो लक्ष्य मौजूदा समय-सीमा से बहुत पहले हासिल करें, ताकि विकासशील देशों के लिए कार्बन स्पेस बचा रहे। उन्होंने दोहराया कि जलवायु वित्त को बिलियन से ट्रिलियन तक ले जाना होगा और नए, अतिरिक्त तथा रियायती फंड उपलब्ध कराने होंगे।

यादव ने यह भी कहा कि तकनीक पर कड़े पेटेंट नियम हटाने होंगे, क्योंकि ये कमजोर देशों को जरूरी जलवायु तकनीकों तक पहुंचने से रोक रहे हैं। यह मांग विकासशील देशों की बढ़ती नाराज़गी को दिखाती है। अमीर देश अब तक हर साल 100 अरब डॉलर देने के अपने वादे को पूरा नहीं कर पाए हैं, और नए वैश्विक जलवायु वित्त लक्ष्य पर भी प्रगति बेहद धीमी है, जबकि यही भविष्य की जलवायु वित्त व्यवस्था तय करेगा। यादव ने भारत की जलवायु उपलब्धियों को विस्तार से बताते हुए कहा कि विकास और पर्यावरण संरक्षण साथ-साथ चल सकते हैं। 2005 के बाद से भारत ने अपनी उत्सर्जन तीव्रता में 36 फीसदी से ज्यादा की कमी की है। भारत की कुल बिजली क्षमता का आधा से ज्यादा हिस्सा अब गैर-जीवाश्म ऊर्जा स्रोतों से आ रहा है। इतना ही नहीं 256 गीगावॉट गैर-जीवाश्म क्षमता के साथ भारत ने अपना 2030 का लक्ष्य पांच साल पहले ही हासिल कर लिया है। उन्होंने इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, न्यूक्लियर मिशन और ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जैसे बड़े ऊर्जा अभियानों का जिक्र किया और कहा कि ये भारत की बढ़ती वैश्विक जलवायु नेतृत्व क्षमता को दिखाते हैं। इसके अलावा, भारत ने प्राकृतिक कार्बन भंडारण को बढ़ाने के लिए समुदायों की भागीदारी से 16 महीनों में 200 करोड़ से अधिक पौधे लगाए हैं। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस (आईबीसीए) के उच्चस्तरीय सत्र में यादव ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण, जलवायु स्थिरता का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने बताया कि बाघ, तेंदुओं जैसी बड़ी बिल्लियां परिस्थितिकी तंत्र की सेहत की प्रहरी होती हैं। जहां ये सुरक्षित होती हैं, वहां जंगल बेहतर होते हैं, घासभूमि स्वस्थ रहती है, जलस्रोत स्थिर रहते हैं और प्राकृतिक कार्बन भंडारण भी बढ़ता है। उन्होंने चेताया कि बड़ी बिल्लियों की संख्या कम होने से पूरा पारिस्थितिकी तंत्र कमजोर होता है और जलवायु के असर को झेलने की क्षमता भी कमजोर पड़ती है। इसलिए उन्होंने आग्रह किया कि भविष्य के एनडीसी में जैव विविधता को एक प्राकृतिक जलवायु समाधान के रूप में शामिल किया जाए। यादव ने कहा, जिसे हम अक्सर वन्यजीव संरक्षण कहते हैं, वह असल में सबसे स्वाभाविक जलवायु कार्रवाई है। भारत दुनिया की सात में से पांच बड़ी बिल्ली प्रजातियों का घर है। भारत ने अपने संरक्षण कार्यों में कई बड़ी सफलताएं हासिल की हैं, जैसे लक्ष्य से पहले बाघों की संख्या दोगुनी करना और एशियाई शेरों की आबादी को बढ़ाना। भारत ने एक व्यापक वन्यजीव डाटाबेस भी तैयार किया है, संरक्षित क्षेत्रों और वन्य गलियारों को विस्तार दिया है और स्थानीय समुदायों को पर्यावरण-आधारित आजीविकाओं से जोड़ा है। यादव ने बताया कि 17 देश आधिकारिक रूप से आईबीसीए से जुड़ चुके हैं और 30 से ज्यादा ने इससे जुड़ने में दिलचस्पी दिखाई है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वन अर्थ, वन वर्ल्ड, वन फ्यूचर की सोच दोहराई। उन्होंने घोषणा की कि भारत 2026 में नई दिल्ली में ग्लोबल बिग कैट्स समिट की मेजबानी करेगा, और सभी देशों को इसमें मिलकर काम करने का आमंत्रण दिया।

अपने वक्तव्यों का समापन करते हुए यादव ने कहा कि दुनिया एक ऐसे समय पर है जब पर्यावरण की नई दिशा तय करनी है, और इसके लिए प्रतियोगिता नहीं बल्कि एकजुटता जरूरी है।

भारत के संविधान पर प्रदर्शनी,औबेदुल्लागंज के बच्चों ने दिखाया हुनर

भोपाल डीबी मॉल की आर्ट गैलरी में ग्लोबल स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, औबेदुल्लागंज और स्वहस्श्वष्ठ संस्था द्वारा आयोजित द कलर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पेंटिंग प्रदर्शनी का आज अत्यंत सफल आयोजन हुआ। संविधान के 76 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित इस विशेष कार्यक्रम को बड़ी संख्या में आगंतुकों ने देखा और सराहा।

कार्यक्रम में प्रमुख रूप से, प्रसिद्ध रंगकर्मी श्री राजीव वर्मा, अंतरराष्ट्रीय सितार वादक सुश्री स्मिता नागदेव, पूर्व डीजीपी(सेवानिवृत्त) श्री अन्वेष मंगलम, सेवा निवृत आईएएस श्री अजातशत्रु श्रीवास्तव, पटेल ग्रुप की निदेशक सुश्री प्रीति पटेल, Career College के निदेशक श्री मनीष राजोरिया, तथा पूर्व भोपाल बार काउंसिल अध्यक्ष श्री पी.सी. कोठारी सहित कई प्रतिष्ठित सामाजिक एवं सांस्कृतिक हस्तियाँ उपस्थित रहीं। औबेदुल्लागंज के बच्चों ने अद्भुत आत्मविश्वास के साथ अपने चित्रों और संविधान के सिद्धांतों को समझाया, जिसे समीक्षकों ने ऐतिहासिक और प्रेरक बताया। अतिथियों ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के इन बच्चों ने अपने गहन ज्ञान, स्पष्ट अभिव्यक्ति और कला कौशल का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है । दर्शकों ने भी प्रदर्शनी को अत्यंत प्रभावशाली और सीख देने वाला अनुभव बताया। आयोजकों के अनुसार यह आयोजन ग्रामीण बच्चों की रचनात्मकता को बड़ा मंच देने और उन्हें लोकतांत्रिक मूल्यों से जोड़ने की दिशा में एक सार्थक और सफल प्रयास है।

जल संचय, जन भागीदारी में खण्डवा जिले को मिला प्रथम पुरस्कार

राष्ट्रीय जल पुरस्कार के तहत खंडवा की कावेश्वर पंचायत को मिला द्वितीय पुरस्कार

इंदौर 6वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार के अंतर्गत नई दिल्ली के विज्ञान भवन में मंगलवार को आयोजित कार्यक्रम में सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत की श्रेणी में खंडवा जिले की कावेश्वर पंचायत को द्वितीय पुरस्कार दिया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने खण्डवा के कलेक्टर श्री ऋषव गुप्ता एवं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. नागार्जुन बी. गौड़ा को पुरस्कार प्रदान किया। कलेक्टर श्री गुप्ता ने बताया कि भारत सरकार के जल शक्ति अभियान- कैच द रेन के तहत शुरू की गई जल संचय, जन भागीदारी पहल में खण्डवा जिले ने जल संरक्षण के क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान स्थापित करते हुए देश में प्रथम स्थान प्राप्त

किया है, इसके लिए खण्डवा जिले को 2 करोड़ रूपये का पुरस्कार मिला है। कलेक्टर श्री गुप्ता ने बताया कि खंडवा जिले की ग्राम पंचायत कावेश्वर में किए गए जल संरक्षण के उल्लेखनीय कार्यों के कारण राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय पुरस्कार के लिए कावेश्वर पंचायत का चयन किया गया है। इसके लिए 1.50 लाख रूपये का नगद पुरस्कार एवं ट्रॉफी प्रदान की गई है। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत द्वारा विगत वर्षों में कावेरी नदी के उद्गम कुंड का जीर्णोद्धार किया गया। साथ ही पंचायत के पहाड़ी क्षेत्र को वाटरशेड के मूल सिद्धांत रिज टू वैली के आधार पर विकसित किया गया। इसके तहत लगभग 50 हेक्टेयर क्षेत्र में कंटूर, 55 गली प्लग, 35 पोखर तालाब, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, हैंडपंप रिचार्ज, बोरवेल रिचार्ज, रिचार्ज शाफ्ट का निर्माण किया गया।

कर्नाटक में गहराता कचरा संकट, हर दिन बिना उपचार के बच रहा 2,567 टन कचरा

कर्नाटक रिपोर्ट में बताया गया है कि ग्रेटर बेंगलुरु क्षेत्र में नौ बड़े डंपसाइट की पहचान हुई है, जिनमें कुल 97.82 लाख मीट्रिक टन पुराना कचरा जमा है, जिसे वैज्ञानिक तरीके से निपटाने की जरूरत है। रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि कर्नाटक में ठोस और तरल कचरे के प्रबंधन के लिए कुल 926 विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की गई हैं। इनमें से 21 परियोजना रिपोर्ट ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी के लिए हैं, जबकि बाकी 905 डीपीआर शहरी निकायों से जुड़ी हैं कर्नाटक में हर दिन 13,269 टन कचरा पैदा हो रहा है, जबकि प्रोसेसिंग क्षमता महज 10,702 टन प्रतिदिन है। यानी 2,567 टन प्रतिदिन का बड़ा अंतर अभी भी मौजूद है। इस प्रोसेसिंग में गीले कचरे में 971 टन और सूखे कचरे में 1,596 टन प्रतिदिन की कमी शामिल है। यह अंतर सभी शहरी निकायों, खासकर ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी (जीबीए) के लिए चुनौती बना हुआ है।

यह जानकारी कर्नाटक के मुख्य सचिव ने 15 नवंबर 2025 को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के समक्ष प्रस्तुत एक विस्तृत रिपोर्ट में दी है। इस रिपोर्ट में कर्नाटक में ठोस कचरा प्रबंधन की स्थिति पर प्रकाश डाला गया है। लम्बे समय से जमा पुराने कचरे के मामले में रिपोर्ट में जानकारी दी है कि कर्नाटक के 223 शहरी निकायों में 231 डंपसाइट मौजूद हैं, जहां करीब 176.08 लाख मीट्रिक टन पुराना कचरा जमा है। अब तक इसमें से 78.24 लाख मीट्रिक टन कचरे का उपचार किया जा चुका है। ग्रेटर बेंगलुरु क्षेत्र में नौ बड़े डंपसाइट की पहचान हुई है, जिनमें कुल 97.82 लाख मीट्रिक टन पुराना कचरा जमा है। इनमें से बेल्लाहल्ली और मित्तगनहल्ली में 42.44 लाख मीट्रिक टन पुराने कचरे को वैज्ञानिक तरीके से ढंका जा चुका है, जबकि बेंगलुरु में 4.43 लाख मीट्रिक टन कचरे का उपचार पूरा किया गया है। बाकी साइटों का काम चल रहा है और सरकार ने दावा किया है कि सभी साइटें अगस्त 2027 तक पूरी तरह तैयार हो जाएंगी। रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि कर्नाटक में ठोस और तरल कचरे के प्रबंधन के लिए कुल 926 विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की गई हैं। इनमें से 21 परियोजना रिपोर्ट ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी के लिए हैं, जबकि बाकी 905 डीपीआर शहरी निकायों से जुड़ी हैं। इन 905 परियोजना रिपोर्टों में से 637 ठोस कचरा प्रबंधन और 268 तरल कचरा प्रबंधन से जुड़ी हैं। रिपोर्ट से यह भी पता चला है कि कर्नाटक ने सभी 637 परियोजना रिपोर्टों को अंतिम रूप दे दिया है, जो 310 शहरी निकायों में सूखे, गीले, पुराने और निर्माण एवं विध्वंस संबंधी कचरे के प्रबंधन से जुड़े हैं। सीवेज उपचार संयंत्रों (एसटीपी) से संबंधित 268 विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में से फिलहाल 109 तैयार हो रहे हैं। सरकार ने एनजीटी को जानकारी दी है कि ये डीपीआर दिसंबर 2026 तक तैयार हो जाएंगे और इनके आधार पर होने वाला निर्माण कार्य दिसंबर 2027 तक पूरा कर लिया जाएगा।

उत्तराखण्ड और झारखण्ड को प्रकृति का विशेष उपहार -राज्यपाल श्री पटेल

राजभवन में मनाया गया दोनों राज्यों का स्थापना दिवस

राज्यों की लोक संस्कृति पर केन्द्रित प्रस्तुतियों ने बटोरी तालिया

भोपाल राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल ने कहा कि उत्तराखण्ड और झारखण्ड को प्रकृति का विशेष उपहार मिला है। यहां पर समृद्ध वन्य जीव और प्राकृतिक संपदा भरपूर मात्रा में है। राज्यपाल श्री पटेल सोमवार को एक भारत-श्रेष्ठ भारत संकल्पना के तहत उत्तराखण्ड और झारखण्ड राज्य स्थापना दिवस कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

राज्यपाल श्री पटेल ने दोनों राज्यों के स्थापना दिवस की सभी को बधाई दी। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के लिए कलाकारों की सराहना की। इस अवसर पर उत्तराखण्ड के राज्यपाल ले.ज. गुरमीत सिंह और झारखण्ड के राज्यपाल श्री संतोष गंगवार के शुभकामना संदेश और दोनों राज्यों की लघु फिल्म का प्रसारण किया गया। राजभवन के सांदीपनि सभागार में राज्यपाल के प्रमुख सचिव डॉ. नवनीत मोहन कोठारी भी मौजूद थे। राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि जहां एक ओर उत्तराखण्ड प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। उसी प्रकार झारखण्ड भी समृद्ध खनिज सम्पदा और लोक संस्कृति के लिए विश्व विख्यात है। महान

जनजातीय नायक और क्रांतिसूर्य भगवान बिरसा मुंडा की कर्म भूमि झारखण्ड, हम सभी के लिए प्रेरक है। उन्होंने कहा कि स्थापना दिवस दोनों राज्यों के गठन की ऐतिहासिक यात्रा का प्रतीक है। भारत की विविधता, संघीय संरचना और एकता की उस शक्ति का भी स्मरण है।

जिसने हमारे देश को दुनिया में विशेष पहचान दी है। यह सांस्कृतिक समारोह नहीं, बल्कि भारत की सामूहिक विकास यात्रा में हमारी सक्रिय भागीदारी का प्रमाण है। हम सभी यहाँ अतिथि बनकर नहीं, बल्कि राष्ट्र-निर्माण के समर्पित सहभागी के रूप में उपस्थित हैं। राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत के सभी राज्यों के स्थापना दिवस को राजभवन में मनाए जाने की पहल अनुकरणीय है। ऐसे आयोजन विविधता में एकता की संवैधानिक भावना को नई ऊर्जा प्रदान करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में गुजरात के केवडिया स्थित स्टेच्यू ऑफ यूनिटी में 01 से 15 नवंबर तक विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। यह भारत की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा और धरोहर को करीब से जानने का अभूतपूर्व और दर्शनीय आयोजन था। राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के दूरदर्शी प्रयासों ने राष्ट्रीय विकास को जन-भागीदारी, सांस्कृतिक पुनर्जागरण और सामूहिक उत्तरदायित्व के साथ जोड़कर नए युग की शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय एकता केवल सीमाओं के विस्तार से नहीं, बल्कि विचारों, संस्कृतियों और समाज के हर वर्ग के सम्मान से सुदृढ़ होती है। इसी भावना का साकार रूप आज का यह संयुक्त समारोह है। 'एक भारत—श्रेष्ठ भारत' अभियान इस राष्ट्रीय भावना की उन्नत अभिव्यक्ति है। राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि यह आयोजन उत्तर और दक्षिण, पूर्व और पश्चिम के बीच केवल भौगोलिक नहीं, बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और भावनात्मक सेतु स्थापित करता है। राज्यपाल श्री पटेल का उत्तराखण्ड कुमायूं समाज भोपाल के अध्यक्ष श्री सुरेश कर्नाटक, गढ़वाली समाज ट्रस्ट भोपाल के अध्यक्ष विजय सिंह नेगी और बिहार सांस्कृतिक परिषद भोपाल के अध्यक्ष श्री राजेश कुमार सिंह ने स्मृति चिन्ह, पुष्प और अंग वस्त्र भेंट कर स्वागत और अभिनंदन किया गया। समारोह में उत्तराखण्ड के कलाकारों ने कुमायूं लोक नृत्यों और महादेव स्तुति की प्रस्तुति दी। झारखण्ड के कलाकारों ने मगही गीत और विभिन्न लोक नृत्यों की सामूहिक प्रस्तुति दी। आकर्षक प्रस्तुतियों का दर्शकों ने जोरदार

प्रदूषण का हॉटस्पॉट बना उत्तर प्रदेश, गाजियाबाद में एक्यूआई 401, हालात 'गंभीर'

गाजियाबाद देश में गाजियाबाद की हवा सबसे खराब रही, जब वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी एक्यूआई 401 रिकॉर्ड किया गया। गौरतलब है कि 16 नवंबर को गाजियाबाद में एक्यूआई 419 दर्ज किया गया था। मतलब कि वहां कल से प्रदूषण में 18 अंकों की गिरावट आई है। हालांकि इसके बावजूद गाजियाबाद में अभी भी स्थिति 'गंभीर' बनी हुई है और वहां गैस-चैम्बर जैसे हालत बने हुए हैं। रुझानों में सामने आया है कि गाजियाबाद की हवा में प्रदूषण के महीन कण (पीएम2.5) पूरी तरह हावी हैं। देखा जाए तो वहां फिजाओं में घुला जहर इतना ज्यादा है कि वो लोगों को बेहद बीमार बना देने के लिए काफी है। गाजियाबाद से स्थिति किस कदर खराब है, इसी बात से समझा जा सकता है कि वहां प्रदूषण का स्तर विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित सुरक्षित सीमा से 2,500 फीसदी अधिक है। दूसरी तरफ देश में नगांव की हवा सबसे साफ है, जहां वायु गुणवत्ता सूचकांक महज 32 रिकॉर्ड किया गया। ऐसे में यदि देश के सबसे प्रदूषित शहर गाजियाबाद की तुलना शिलांग से करें तो वहां स्थिति 12 गुणा खराब है।

कॉप-30 वेबसाइटों का बढ़ रहा है डिजिटल कार्बन फुटप्रिंट, चौंकाने वाला खुलासा

नई दिल्ली। दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हर साल आयोजित होने वाले संयुक्त राष्ट्र के कॉनफ्रेंस ऑफ द पार्टीज (कॉप) सम्मेलनों का उद्देश्य पर्यावरण की रक्षा करना है। लेकिन एक नई शोध रिपोर्ट ने एक चौंकाने वाला तथ्य उजागर किया है, जिन सम्मेलनों में पर्यावरण की सुरक्षा पर चर्चा होती है, उनकी वेबसाइटें स्वयं कार्बन उत्सर्जन कर रही हैं।

ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए इस अध्ययन को प्लोस क्लाइमेट नामक पत्रिका में प्रकाशित किया गया है। शोध के अनुसार, 1995 से लेकर 2024 तक कॉप सम्मेलनों की वेबसाइटों के कार्बन उत्सर्जन में 13,000 फीसदी से अधिक की वृद्धि हुई है। शोधकर्ताओं ने इंटरनेट के पुराने अभिलेखों (वेब आर्काइव) का उपयोग किया, जिनमें वेबसाइटों के पुराने संस्करण संरक्षित रहते हैं। इन अभिलेखों का विश्लेषण करके टीम ने पिछले 30 सालों में कॉप वेबसाइटों के आकार, संरचना और कार्बन उत्सर्जन में हुए बदलावों को मापा।

इस अध्ययन में पाया गया कि 1995 से लेकर 2008 (कॉप-14) तक वेबसाइटें अपेक्षाकृत हल्की थीं। उस समय एक पृष्ठ को देखने पर औसतन 0.02 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड (सीओ2) उत्सर्जित होता था। लेकिन 2009 के बाद से, यानी कॉप-15 से वेबसाइटों का डिजिटल भार और उनका कार्बन प्रभाव दोनों तेजी से बढ़ने लगे।

1997 में आयोजित कॉप-3 सम्मेलन (पहला वर्ष जिसके लिए इंटरनेट डेटा उपलब्ध है) के दौरान वेबसाइट पर हुई कुल विजिट से लगभग 0.14 किलोग्राम सीओ2 उत्सर्जन हुआ था, यह मात्रा एक परिपक्व पेड़ द्वारा दो दिनों में अवशोषित किए गए कार्बन के बराबर है। इसके विपरीत, 2024 के कॉप-29 सम्मेलन की वेबसाइट से कुल उत्सर्जन लगभग 116.85 किलोग्राम सीओ2 तक पहुंच गया। इस मात्रा को अवशोषित करने में 10 परिपक्व पेड़ों को पूरे एक वर्ष का समय लगेगा। यानी पिछले लगभग 27 वर्षों में डिजिटल कार्बन उत्सर्जन में 83,000 फीसदी से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है। मल्टीमीडिया कंटेंट का बढ़ना- अब वेबसाइटों पर वीडियो, एनिमेशन, इंफोग्राफिक और हाई-रिज़ॉल्यूशन इमेज का प्रयोग बहुत बढ़ गया है। वेबसाइट का जटिल ढांचा- नई तकनीकों और डिजाइन फ्रेमवर्क्स से वेबसाइटें आकर्षक तो बनती हैं, पर साथ ही डेटा लोड बढ़ जाता है। सर्वर की ऊर्जा खपत- कई वेबसाइटें अभी भी नवीकरणीय ऊर्जा पर आधारित सर्वरों पर नहीं चल रही हैं, जिससे बिजली की खपत और कार्बन उत्सर्जन दोनों बढ़ जाते हैं। ऑनलाइन ट्रैफ़िक में वृद्धि- कॉप सम्मेलनों की लोकप्रियता के कारण वेबसाइट पर लाखों लोग एक साथ पहुंचते हैं, जिससे इंटरनेट डेटा ट्रांसफर और ऊर्जा की मांग बढ़ जाती है। वेबसाइट का आकार सीमित करें- अनावश्यक चित्र, वीडियो या जटिल एनीमेशन से बचें। कोड और डिजाइन को अनुकूल बनाएं- साइट को हल्का और तेज लोड होने वाला बनाया जाए। नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करें- वेबसाइटों को ऐसे सर्वरों पर होस्ट करें जो सौर या पवन ऊर्जा से संचालित हों। शोध के मुताबिक, औसतन सात गुना अधिक उत्सर्जन, एक सामान्य वेबसाइट की तुलना में कॉप साइटें प्रति पेज अधिक ऊर्जा खर्च करती हैं। शोधकर्ताओं ने अपनी विश्लेषणात्मक कंप्यूटर कोड को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया है ताकि अन्य संस्थान भी अपनी वेबसाइटों के ऐतिहासिक और वर्तमान पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन कर सकें। शोध पत्र में शोधकर्ता के हवाले से कहा गया है कि वेबसाइटों का डिजिटल पदचिह्न अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है, यहां तक कि वे संगठन भी इसे नजरअंदाज करते हैं जो पर्यावरण की रक्षा की बात करते हैं। हमारा शोध दिखाता है कि डिजिटल उपस्थिति की एक लागत होती है, जिसे समझना और घटाना जरूरी है। शोध में कहा गया है कि आजकल कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) पर बहुत चर्चा होती है, लेकिन वेबसाइटें अब भी इंटरनेट के सबसे बड़े और स्थायी डिजिटल माध्यमों में से एक हैं। इनका पर्यावरणीय प्रभाव बहुत व्यापक है। शोध के मुताबिक, औसतन सात गुना अधिक उत्सर्जन, एक सामान्य वेबसाइट की तुलना में कॉप साइटें प्रति पेज अधिक ऊर्जा खर्च करती हैं। आज इंटरनेट वैश्विक कार्बन उत्सर्जन का लगभग तीन फीसदी हिस्सा है। इस संदर्भ में, डिजिटल स्थिरता अब उतनी ही जरूरी हो गई है जितनी ऊर्जा, परिवहन या उद्योग क्षेत्र में है। यदि संस्थान और सरकारें अपनी डिजिटल नीतियों में पर्यावरणीय दृष्टिकोण को शामिल करें, तो इंटरनेट को भी हरित (ग्रीन) बनाया जा सकता है। कॉप वेबसाइटों का यह अध्ययन हमें यही याद दिलाता है कि जलवायु परिवर्तन से लड़ाई केवल भौतिक दुनिया में नहीं, बल्कि डिजिटल दुनिया में भी लड़ी जानी चाहिए।

खरगोन कलेक्टर सुश्री मित्तल सर्वश्रेष्ठ जिले का 6वे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 से सम्मानित

इंदौर इंदौर संभाग के खरगोन जिला कलेक्टर सुश्री भव्या मित्तल को जल संरक्षण कार्यों के लिए पश्चिम क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ जिले का 6वे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। जिले में 4.21 लाख जलसंरचनाएं निर्मित कर 2.31 करोड़ घनमीटर जल भंडारण क्षमता बढ़ाई गई है। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में कलेक्टर सुश्री मित्तल को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री सीआर पाटिल भी उपस्थित थे।

उल्लेखनीय है कि खरगोन जिले में नदियों के संरक्षण और तटों के जीर्णोद्धार के लिए उल्लेखनीय कार्य किए गए हैं। नर्मदा, नानी, वंशावली और बोराड़ नदियों के 8000 हेक्टेयर क्षेत्रफल के क्षरित लैंडस्केप को स्टॉप डैम, चेक डैम, खेत तालाब, लूस बोल्डर स्ट्रक्चर के माध्यम से संरक्षित किया गया। सहायक नदियां, जो पहले नवंबर या दिसंबर तक सूख जाती थीं, अब अप्रैल माह तक अविरल रहती हैं। कुंदा नदी के जलग्रहण क्षेत्र के किनारे 627 स्थानों से अतिक्रमण हटाया गया है। अतिक्रमण से मुक्त कराई गई 106 एकड़ भूमि में निधिवन स्थापित कर पर्यटन स्थल बनाया गया है। जिले में काउंटर ट्रेंच, चेक डैम, पर्कोलेशन टैंक, गली प्लग और गैबियन जैसे कुल 4,21,182 कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं का निर्माण किया गया जिससे भूजल स्तर में वृद्धि हुई है। जिले के सभी जल निकायों की मैपिंग कर राजस्व अभिलेखों में प्रविष्टि की गई है और 45 ऐतिहासिक बावड़ियों का जीर्णोद्धार किया गया है। जिले में सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत 48,975 हेक्टेयर क्षेत्रफल आता है, जिसमें आंकलन वर्ष में कुल 3,290 हेक्टेयर नया क्षेत्रफल जोड़ा गया है; 37,042 कृषकों को इसका लाभ मिल रहा है। जिले में 156 नए अमृत सरोवर सहित 2,31,75,828 घनमीटर की जल भंडारण क्षमता बनाई है। ग्रामीण विकास विभाग की वाटरशेड विकास- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 एवं मनरेगा से उपरोक्त कार्यों का क्रियान्वयन प्रमुखता से किया गया है। जिले में अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण के लिए 15 इकाइयां, 4 मलजल उपचार संयंत्र, 94 अपशिष्ट स्थिरीकरण कुंड संचालित हैं। 5400 हेक्टेयर में 30 लाख वृक्षों का पौधारोपण किया गया है जिनमें से 95 प्रतिशत वृक्ष जीवित हैं। मनरेगा योजनांतर्गत 3,80,000 पौधे और निजी फलोद्यान में 2,66,412 अमरूद के पौधे लगाए गए हैं, जिससे भूजल स्तर में वृद्धि हुई है। जल संरक्षण और प्रबंधन की दिशा में 2,277 सफाई अभियान, 605 क्षमता निर्माण कार्यशाला, 200 ग्राम पंचायतों में कलश यात्रा का आयोजन, 147 जल चौपाल का आयोजन कर नागरिकों और शासकीय सेवकों का जल संरक्षण के प्रति जागरूक किया गया है।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक सोनल मेहता केलिए प्रतीक्षा ग्राफिक्स, 127 देवी अहिल्या मार्ग, इंदौर (म.प्र.) से मुद्रित एवं 209-बी शहनाई रेसीडेंसी-2 कनाड़िया रोड इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक: डॉ. सोनल मेहता फोन : 0731-2595008 Mail.sonal12mehta@yahoo.co.in 9755040008